बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 223

प्रदूषण: कार्य योजना जरूरी

दीवाली के दिन पटाखों के इस्तेमाल से हर वर्ष भयंकर प्रदूषण हो जाता है, फसल अवशेष जलाए जाने से हर वर्ष करीब एक महीने तक प्रदूषक तत्त्व उत्सर्जित होते हैं और परिवहन स्रोतों के माध्यम से तो दिल्ली में पूरा वर्ष भारी प्रदूषण फैलता है। न्यायपालिका जहां हर वर्ष दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर आंशिक रूप से अंकुश लगाने में कामयाब रही, वहीं फसल अवशेष जलाने पर उसका प्रतिबंध प्रभावी नहीं साबित हुआ। साल भर होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयास भी उतने प्रभावी नहीं दिखे। केंद्र सरकार ने जहां इस विषय पर खामोशी बरती है, वहीं दिल्ली और पंजाब की राज्य सरकारें एक दूसरे को दोषी ठहराने में व्यस्त हैं। स्पष्ट है कि सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा तदर्थ उपाय अपनाए जाने के बजाय एक व्यापक और समन्वित कार्य योजना की आवश्यकता है। इसके लिए हवा की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी होगी और प्रदूषण के स्रोतों पर भी नजर रखनी होगी। इस दिशा में हालांकि व्यापक अकादमिक शोध किया गया है लेकिन परिणाम इसलिए अलग-अलग रहे क्योंकि हर शोध में अलग परिभाषा, मानकों और अवधि का प्रयोग किया गया।

व्यापक कार्य योजना में सरकार या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हवा की गुणवत्ता को लेकर एक आधिकारिक रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें साल भर प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषक तत्त्वों की जानकारी हो। रिपोर्ट में हर स्रोत की जानकारी हो और सरकार इसे स्वीकृति प्रदान करे। हमारे आसपास की हवा ही हमारे स्वास्थ्य और जीवन को नुकसान पहुंचा रही है और प्रदूषण के स्रोत का पता लगाकर हम विशिष्ट कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। आधिकारिक मंजूरी मिलने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ मिलकर काम कर सकेंगे। प्रदूषण को लेकर ऐसी आधिकारिक और समयबद्ध रिपोर्ट को आधार बनाकर व्यवस्थित कार्य योजना की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

इस योजना के तहत भी सरकार की विभिन्न शाखाओं और अलग-अलग चरणों में अलग-अलग कार्य आवंटित करने होंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार को अपने दायरे में आने वाली 8,000 किलोमीटर सड़क के ऊपरी हिस्से का रखरखाव करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना चाहिए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच कड़ी करनी चाहिए और ईंट का प्रयोग बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली के आसपास के करीब 30 कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्सर्जन मानकों का पालन करें। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के किसानों को पानी की खपत और प्रदूषण बढ़ाने वाले धान की खेती से अन्य पर्यावरण के अनुकूल फसलों का रुख करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसानों की आर्थिकी में बदलाव लाना होगा ताकि फसल अवशेष को एकत्रित करना और उसका निपटान करना, जलाने की तुलना में अधिक बेहतर साबित हो। न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन वाले वाहन मसलन ई-स्कूटर आदि की दिशा में तत्काल बढ़ना होगा। दिल्ली के कई नगरीय विभागों को साथ आकर कचरा संग्रहण और निस्तारण की किफायती व्यवस्था कायम करनी चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र तथा अन्य प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों में नियम तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसी कार्य योजना हकीकत के करीब होनी चाहिए और उसे समयबद्ध तरीके से अंजाम देना होगा। इसकी निगरानी सरकार और नागरिक समाज दोनों को करनी होगी।

यदि क्रियान्वयन कमजोर हुआ तो कोई कार्य योजना सफल नहीं होगी। प्रदूषक तत्त्वों का मापन नीतिगत दृष्टि से अहम है लेकिन प्रदूषण करने वालों को रोकना क्रियान्वयन की दृष्टि से कहीं अधिक महत्त्व रखता है। उपग्रहों के माध्यम से रियल टाइम रिमोट सेंसिंग तस्वीरें खींचना तथा ऐसे अन्य तरीकों को निगरानी विकल्पों में शामिल किया जाना चाहिए। तदर्थ तरीके से काम करने और एक दूसरे पर अंगुली उठाने का वक्त चला गया।

अजय मोहंती

भारत के पड़ोस में चीन का बढ़ता दबदबा

अगर भारत अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी आर्थिक प्रगति की गति तेज करनी होगी और उसमें निरंतरता लानी होगी। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रही हैं **अनिता इंदर सिंह**

चीन ने अपनी आर्थिक ताकत के बल पर भारत के उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में पैठ मजबूत की है। उसने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए। इन देशों के साथ चीन के दीर्घावधि के लंबे और मजबूत रिश्ते तथा उसका सुगम संचार बीते छह महीनों के दौरान एकदम उभरकर सामने आया है। नेपाल के साथ चीन के मजबूत रिश्ते राष्ट्रपति शी चिनफिंग की हालिया काठमांडू यात्रा के दौरान साफ नजर आए। अक्टूबर के मध्य में भारत की यात्रा के तुरंत बाद वह नेपाल गए। इससे पहले जुलाई में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पेइचिंग की आधिकारिक यात्रा पर गई थीं। अप्रैल में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची ने पेइचिंग में बेल्ट ऐंड रोड (बीआरआई) की बैठक के दौरान व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

ये तीनों देश भारत के मित्र राष्ट्र हैं लेकिन क्या अधिक समृद्ध चीन के साथ उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत हैं? भारत के उलट इन तीनों ने चीन की बीआरआई पहल में शिरकत कर ली है। इस पहल का लक्ष्य चीन के आर्थिक और सामरिक हितों को आगे बढ़ाना है। चीन इन तीनों देशों में सबसे अधिक निवेश करने वाला देश है। इन देशों में से दो बांग्लादेश और म्यांमार चीन के शीर्ष तीन हथियार खरीदार देशों में शुमार हैं। म्यांमार अपने 60 फीसदी हथियार चीन से खरीदता है जबकि बांग्लादेश अपने 70 फीसदी हथियार चीन से खरीदता है। चीन के लिए सभी देश महत्त्वपूर्ण हैं। ये दोनों देश बंगाल की खाड़ी में चीन की पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जहां से वह भारत को चुनौती दे सकता है। बीआरआई चीन की पिछली 40 साल की प्रगति का परिचायक है। हकीकत यह है कि चीन ने इन तीनों मुल्कों के साथ बेहतरीन व्यापार और निवेश रिश्ते कायम किए हैं जबकि भारत ऐसा नहीं कर पाया। चीन ने अहम क्षेत्रों में निवेश करके अपनी जगह बनाई है जबकि भारत इन क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं दे सका।

शी चिनफिंग पिछले दो दशक में नेपाल की यात्रा पर जाने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति बने। उनकी इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक अहम समझौते में चीन के तिब्बत और नेपाल तक हिमालय के रास्ते रेल संचार को बढ़ावा देने की बात शामिल है। शी चिनफिंग ने नेपाल को आश्वस्त किया है कि रेल परियोजना उसे चारों ओर से जमीन से घिरे मुल्क से बदलकर जमीन से जुड़े देश में तब्दील कर देगी।

नेपाल और चीन ने पुलिस, खुफिया विभाग, सीमा प्रबंधन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग के लिए सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने नेपाल में राजमार्गों, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों में सुधार में भी मदद की है। शी चिनफिंग की यात्रा के पश्चात घोषणा की गई कि चीन, अगले तीन वर्ष के दौरान नेपाल की सेना को करीब 2.1 करोड़ डॉलर की आपदा राहत सामग्री देगा।

उधर, भारत के पूर्व में चीन और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते गत जुलाई में साफ नजर आए जब हसीना और शी ने ढेर सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए और ऐतिहासिक हिचक को पीछे छोड़ दिया। सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया था। बांग्लादेश की आजादी की उस लड़ाई में चीन पाकिस्तान के साथ था। उसने संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रवेश को वीटो किया और सन 1976 में नए देश को मान्यता प्रदान की।

बहरहाल, इतिहास बदलने को है। दक्षिण एशिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में बांग्लादेश ने चीन के 38 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत किया है। पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर के निवेश के बाद दक्षिण एशिया में यह चीन का सबसे बड़ा निवेश है। इतना ही नहीं चीन ने खुद को बांग्लादेश के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार के रूप में स्थापित किया है। दोनों देशों के बीच 2017-18 में कुल 12.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। उस वर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 9.5 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। बांग्लादेश के आयात का 22 फीसदी चीन से होता है जबकि केवल 1.3 फीसदी भारत से। बांग्लादेश के कुल निर्यात का महज 1.7 फीसदी भारत को मिलता है जबकि 2.3 फीसदी चीन को जाता है।

म्यांमार के साथ चीन के रिश्ते इस बात की कहानी कहते हैं कि उसके व्यापारिक साझेदार के रूप में और बुनियादी ढांचा तथा बंदरगाह विकास के क्षेत्र में चीन की क्या भूमिका रही। म्यांमार के आयात का एक तिहाई चीन से और महज 5.2 फीसदी भारत से होता है। उसके निर्यात का 33 फीसदी चीन जाता है जबकि केवल 3.5 फीसदी भारत।

चीन ने म्यांमार के पश्चिमी तट पर क्याउक्पू में गहरे सागर में बंदरगाह बनाने में भारी-भरकम निवेश किया है। यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से भी बहुत अधिक मायने रखता है क्योंकि चीन के युन्नान प्रांत को जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और तेल आदि यहीं से जाते हैं। इससे चीन को पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति पाने में मदद मिलेगी और उसे भारी भीड़ वाले मलक्का की खाड़ी वाले रास्ते से निजात भी। चीन क्याउक्पू में एक आर्थिक क्षेत्र विकसित कर रहा है।

बीआरआई के कर्ज के जाल और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से परियोजनाओं को जोखिम उत्पन्न होने पर चीन ने लचीला रुख अपनाया है। गत वर्ष बांग्लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद 226 किलोमीटर लंबे ढाका-सिलहट मार्ग परियोजना से चीन को बाहर कर दिया था। कंपनी को उस राजमार्ग को चौड़ा करने का अनुबंध मिला था। बांग्लादेश को परियोजना की लागत से भी शिकायत थी। अब वह कम लागत पर खुद उस सड़क का निर्माण कर रही है।

इस बीच म्यांमार ने क्याउक्पू बंदरगाह को लेकर योजनाओं को सीमित किया है। परियोजना लागत में भारी कमी की गई है। चीन ने पहले इस परियोजना के 7.3 अरब डॉलर की मांग रखी थी लेकिन म्यांमार द्वारा अनुरोध करने के बाद इसे घटाकर 1.3 अरब डॉलर कर दिया गया।

भारत इन तीनों अहम पड़ोसियों को जरूरी वित्तीय मदद मुहैया नहीं करा पा रहा है। लालफीताशाही और परियोजना क्रियान्वयन के क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन ने इसमें और इजाफा किया है। भारत में ये समस्याएं आम हैं और ये हमारी एक्ट ईस्ट नीति के क्रियान्वयन को भी धीमा करती हैं। भारत को इन हकीकतों को अच्छी तरह समझना होगा। यदि भारत चाहता है कि वह इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाए तो उसे अपनी आर्थिक प्रगति तेज करनी होगी और उसे स्थायित्व भी प्रदान करना होगा। उसे अपने पड़ोसियों से किए गए वादों पर खरा उतरना होगा। तब तक लगता यही है कि चीन नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी बढ़त जारी रखेगा।

(लेखिका सेंटर फॉर पीस ऐंड कन्फ्लिक्ट रेजलूशन, नई दिल्ली की संस्थापक प्रोफेसर हैं)

इन्फोसिस खुलासा मामले में नारायण मूर्ति की चुप्पी

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

इन्फोसिस के बोर्ड से आर शेषशायी और विशाल सिक्का की विदाई के कुछ ही दिन बाद 28 अगस्त, 2017 को एन आर नारायण मूर्ति ने कंपनी के शेयरधारकों के नाम एक लंबा पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था, 'जब संगठन के संचालन के तौर-तरीकों को लेकर बादल घिरे हों तो हमें बोलना चाहिए।' उन्होंने कंपनी प्रबंधन को यह सलाह भी दी थी कि 'जब भी संदेह में हों तो बिना किसी हिचक के अपनी बात रखें क्योंकि इन्फोसिस सभी शेयरधारकों की नजरों में सर्वाधिक सम्मानित कंपनी बने रहना चाहती है।'

कंपनी जगत में भारत की सर्वाधिक सम्मानित शख्सियतों में शामिल व्यक्ति ने यह सही सलाह दी थी। लेकिन निश्चित रूप से इस पर बहस हो सकती है कि मूर्ति क्या खुद अपनी बात पर बने रहे हैं? अक्टूबर में इन्फोसिस ने कंपनी के भीतर अनैतिक गतिविधियों के आरोप लगाने वाले दो व्हिसल ब्लोअर के बारे में शेयरधारकों को सूचित करने में तीन हफ्ते का वक्त लगा दिया।

मूर्ति पुराने निदेशक मंडल और उसके मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) के बारे में अपनी आलोचना को लेकर काफी सख्त थे, वहीं इस बार की उनकी चुप्पी बहरा करने वाली है। इसकी उलटी दलील यह है कि मूर्ति इस बार समय से पहले इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्फोसिस का एक गैर-कार्यकारी चेयरमैन मौजूद है। लेकिन इस दलील में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि पिछली बार भी इन्फोसिस के चेयरमैन के तौर पर शेषशायी पदासीन थे। लेकिन वह भी मूर्ति को सार्वजनिक रूप से आलोचनात्मक बयान देने से नहीं रोक पाया।

पिछली बार एक व्हिसल ब्लोअर ने इजरायली ऑटोमेशन कंपनी पनाया के 20 करोड़ डॉलर में किए गए अधिग्रहण में अनियमितता के आरोप लगाए थे। मूर्ति ने उस सौदे को मंजूरी देने के बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाने के साथ ही पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी राजीव बंसल को दिए गए बहुत अधिक सेवेरेंस पैकेज की तुलना 'हश मनी' (मुंह बंद रखने के लिए दी गई रिश्वत) से भी की थी। उन्होंने व्हिसल ब्लोअर के पत्र का हवाला भी दिया था जिसमें बंसल को दिए पैकेज के बारे में शेयरधारकों से झूठ बोलने का शेषशायी पर आरोप भी लगाया था। इसके अलावा उन्होंने सिक्का के कामकाज के तरीकों को लेकर भी खुले सवाल उठाए थे।

यह बिल्कुल अलग बात है कि अंदरूनी एवं बाहरी जांचों में सिक्का को कदाचार के आरोपों से सर्वसम्मति से बरी कर दिया गया। इसके पहले कानूनी फर्म गिब्सन, डन ऐंड क्रचर ने यह नतीजा निकाला था कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो वर्ष 2015 में हुए पनाया के अधिग्रहण में सिक्का या किसी भी अन्य इन्फोसिस कर्मचारी के लाभान्वित होने का उल्लेख करे। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने भी कहा है कि कंपनी को पनाया के विवादित सौदे में गड़बड़ी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। यह बयान एक तरह से सिक्का और तत्कालीन बोर्ड को क्लीन चिट देता है। इसने पनाया को लेकर उपजे विवाद के बाद कंपनी के तत्कालीन शीर्ष प्रबंधन एवं बोर्ड में किए गए व्यापक फेरबदल को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। यह अहम है कि कंपनी बोर्ड ने गिब्सन की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मूर्ति की मांग नहीं मानी।

हालात इस बार भी कुछ खास अलग नहीं हैं। खुद को 'एथिकल इम्प्लॉइज' बताने वाले कुछ कर्मचारियों ने इन्फोसिस के बोर्ड एवं अमेरिका के बाजार नियामक को लिखे पत्र में यह आरोप लगाया है कि मौजूदा सीईओ सलिल पारेख मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए लेखा-कार्य में गड़बड़ी कर रहे हैं। इस बारे में मीडिया में खबरें आने के बाद ही मौजूदा चेयरमैन ने यह माना कि बोर्ड के एक सदस्य के पास सितंबर में दो अनाम पत्र आए थे जिनमें कुछ 'सामान्य तरह के आरोप' लगाए गए हैं और इन दोनों पत्रों को ऑडिट समिति के समक्ष 10 अक्टूबर को रखा भी गया था।

इसमें इसका जिक्र नहीं किया गया कि शिकायती पत्र मिलने और इसे ऑडिट समिति को सौंपे जाने के बीच एक लंबा फासला रहा है। स्टॉक एक्सचेंजों को तो काफी बाद में इसकी जानकारी दी गई जबकि यह स्पष्ट था कि इन्फोसिस के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रभावित करने की पूरी क्षमता इस सूचना में थी।

यह सच है कि इन्फोसिस ने कानूनी प्रावधानों का पालन किया है और शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में इसका जिक्र भी किया है। लेकिन सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी की बहुचर्चित परंपराएं नदारद थीं। खासकर उस समय जब कंपनी की अपनी 'खुलासे के लायक' नीति ही कह रही थी कि किसी व्हिसल ब्लोअर से मिली शिकायत अगर बाहरी एजेंसी से जांच के लायक पाई जाती है तो उसके बारे में शेयरधारकों को भी जानकारी दी जानी चाहिए।

शेयर बाजार में ऐसी अफवाहें हैं कि बाजार में कुछ समूह ऐसे हो सकते हैं जिन्हें व्हिसलब्लोअर के पत्रों में लिखी बातों की जानकारी पहले से रही हो। भले ही इस अटकल पर बहुत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए लेकिन यह एक पहेली ही है कि 11 अक्टूबर को तिमाही नतीजे घोषित करने वाले इन्फोसिस बोर्ड ने इन पत्रों के बारे में खुलासा क्यों नहीं किया? अगर इन पत्रों के बारे में न बताने की वजह यह थी कि प्रबंधन अपने अच्छे प्रदर्शन से ध्यान बंटाने वाली कोई भी बात नहीं लाना चाहता था तो वह एक अपरिपक्व निर्णय ही था।

वैसे जांच जारी होने के समय गड़बड़ी का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है लेकिन यह सच है कि इन्फोसिस के बोर्ड ने अपने संस्थापक नारायण मूर्ति की 'बिना हिचक के खुलासा करने' की सलाह नहीं मानी है। इस बात को एक हद तक समझा जा सकता है लेकिन मूर्ति की चुप्पी परेशान करने वाली है।

कानाफूसी

कमल नाथ का आशावाद

तमाम शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ इन दिनों काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी है। उन्होंने हाल ही में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस राज्य विधानसभा में जल्द ही अपने सदस्यों की संख्या में दो-तीन का इजाफा कर सकती है। दरअसल अब कांग्रेस की निगाहें पवई विधानसभा सीट पर टिक गई हैं जो हाल ही में खाली हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने हाल ही में पवई से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी को सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें एक आपराधिक मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। सचिवालय ने निर्वाचन आयोग को भी सूचित कर दिया है कि सीट खाली हो चुकी है और वहां उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। हाल ही में भोपाल की एक अदालत ने लोधी तथा 12 अन्य लोगों को सन 2014 में एक तहसीलदार पर हमला करने के मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई। इससे पहले कांग्रेस ने झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को पराजित कर अपनी स्थिति में सुधार किया था।

आपका पक्ष

नई विदेश व्यापार नीति की जरूरत

केंद्र सरकार के सामने एक के बाद एक आर्थिक चुनौती बढ़ती जा रही है। हाल में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आठ बुनियादी उद्योग में से सात उद्योगों में 5.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं के खिलाफ फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक भारत को अगले चार माह में अपनी निर्यात प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं को बंद करना होगा। भारत को अगले छह माह में सभी सेज योजनाओं को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। भारत ने भरोसा दिलाया है कि वह इस साल के अंत तक नई विदेश व्यापार नीति लेकर आएगा जो डब्ल्यूटीओ के तय नियमों के आधार पर होगी। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार नई विदेश व्यापार नीति लाई थी जिसमें वैश्विक निर्यात का लक्ष्य 3.4 प्रतिशत रखा गया था। लेकिन वर्तमान में देश का वैश्विक निर्यात मात्र 1.7 प्रतिशत है। हाल में सरकार ने वर्ष 2025 तक एक खरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है जबकि वैश्विक सुस्ती के कारण देश का घटा है। भविष्य में सरकार निर्यात प्रोत्साहन में आर्थिक छूट नहीं दे सकेगी जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती होगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सरकार को इस वक्त

देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निर्यात बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है

अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का फायदा उठाकर दर में कटौती करनी चाहिए। साथ ही दर लगाने की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। निर्यात नीति में आज भी 35 से 40 वर्ष पुराने नियमों को अपनाया जा रहा है इसे भी सरलीकरण करने की आवश्यकता है। ब्याज दरों में भी कटौती की आवश्यकता है ताकि उत्पाद लागत में कमी आए। देश को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में वृद्धि की आवश्यकता है।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

पर्यावरण को बचाने की हो पहल

मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से दोहन करके अपने विकास का रास्ता तैयार किया जिसका परिणाम अब गंभीर रोग के रूप में सामने आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली तथा एनसीआर का वातावरण इतना जहरीला हो चुका है कि अब लोगों को घर से निकलने से मना किया जा रहा है। शहरों में बढ़ते वाहनों की संख्या, एसी, फ्रिज तथा पटाखों के इस्तेमाल से हमने अपने शहर को प्रदूषित कर रहे हैं। देश में पर्यावरण को सही रखने के लिए 33 प्रतिशत वनों की आवश्यकता है। मगर आज भी हम 23 प्रतिशत पर अटके हुए हैं। ऐसी स्थिति में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना लाजिमी है। लेकिन अब खतरे की आहट मिल चुकी है तथा यह समय लोगों को संभलने का है क्योंकि आज दिल्ली प्रदूषित हुई है, आने वाले समय में अन्य शहर की स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। देश के सबसे खराब वायु प्रदूषण में पटना का सातवां स्थान है। इसका मुख्य कारण सड़कों पर दौड़ रही पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, औद्योगिक कारखाने, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई आदि है। युवाओं को चाहिए कि बदलाव की तासीर लिखे। उन्हें वाहनों का कम इस्तेमाल करने के साथ पौधरोपण को मासिक कार्यक्रम बनाना होगा। शिक्षा की बुनियाद केवल बड़े आदमी बनने के लिए नहीं बल्कि धरती को बचाने और सिंचित करने वाली भी होनी चाहिए।

शिव द्विवेदी, बक्सर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।